



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 222]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16 2009/ज्येष्ठ 26, 1931

No. 222]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2009/JYAISTHA 26, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जाँच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2009

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित बेरियम कार्बोनेट के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच की शुरुआत।

सं. 14/18/2009-डीजीएडी.—मै. अतियप्पा कैमिकल्स प्रा. लि., मै. एलाक कैम. इंडस्ट्रीज प्रा. लि., मै. प्रेम कैमिकल इंडस्ट्रीज तथा मै. विक्ट्री कैमिकल्स लि. ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन. गण. (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित “बेरियम कार्बोनेट” (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया है और इस संबंध में पाटनरोधी जाँच की शुरुआत करने तथा पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

विचाराधीन उत्पाद

2. विचाराधीन उत्पाद बेरियम कार्बोनेट है। श्वेत पाउडर तथा खेदार रूप में बेरियम कार्बोनेट एक हानिकारक, गैर-प्रज्वलनशील अकार्बनिक रसायन है जिसका रासायनिक सूत्र $BaCO_3$ है और यह बेराइट्स जो एक खनिज उत्पाद है, से निर्मित होता है। बेरियम कार्बोनेट के निम्नलिखित अनुप्रयोग हैं :

- कास्टिक सोडा उद्योग में ब्राइन सॉल्यूशन का शुद्धिकरण।
- कठोर फेराइट रिंग मैग्नेट्स, टेलीविजन ग्लास शेल, न्यूट्रल ग्लास लैम्प्स, हीट ट्रीटमेंट सॉल्ट तथा अन्य बेरियम सॉल्ट, चूहे मारने के जहर, सिरैमिक ग्लेजेज तथा वेल्लिंग फ्लक्स के उत्पादन में।
- फ्लक्स, मैटिंग तथा क्रिस्टलीकरण एजेंट के रूप में प्रयुक्त होता है तथा कुछ ऐसे अनोखे रंगों, जो अन्य उपायों से आसानी से नहीं बनाए जा सकते हैं, के निर्माण के लिए चुनिंदा रंजक ऑक्साइड के साथ प्रयोग किया जाता है।
- कच्ची सामग्री में उपस्थित विलेय सल्फयूरिक सॉल्ट को अविलेय बेरियम सल्फेट में परिवर्तित करने की अपनी विशेषता के कारण हैवी क्ले सिरैमिक उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त होता है।
- ईट, टाइल, मिट्टी के बर्तन तथा पॉटरी उद्योगों में विलेय सॉल्ट (कैल्शियम तथा मैग्नीशियम सल्फेट) के अवक्षेप, जिससे प्रस्फुटन होता है, के लिए बेरियम कार्बोनेट मिट्टी के साथ मिलाया जाता है।

3. विचाराधीन उत्पाद अध्याय 28 के अंतर्गत शामिल एक अकार्बनिक रसायन है। इसका आयात सीमाशुल्क वर्गीकरण के अध्याय 28 के उपशीर्ष सं. 28366000 के अंतर्गत किया जाता है। यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

घरेलू समान वस्तु

4. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से निर्यातित वस्तुओं में कोई विशेष अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु तथा संबद्ध देश से आयातित वस्तु भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य विशेषताओं के रूप में समनुरूप हैं। दोनों वस्तुएँ तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ताओं ने वैकल्पिक रूप से दोनों का प्रयोग किया है।

5. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु को उपर्युक्त नियमावली के अर्थ के भीतर संबद्ध देश से आयातित वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग तथा उसका मत

6. मै. अतियप्पा कैमिकल्स प्रा. लि., मै. एलाक कैम. इंडस्ट्रीज प्रा. लि., मै. प्रेम कैमिकल इंडस्ट्रीज तथा मै. विक्ट्री कैमिकल्स लि. द्वारा यह आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से दायर किया गया है। आवेदक घरेलू उत्पादकों ने क्षति तथा लागत निर्धारण संबंधी सूचना प्रस्तुत की है। इस आवेदन का समान वस्तु के अनेक घरेलू उत्पादकों, यथा मै. अमरावती कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स प्रा. लि., हैदराबाद, मै. भार्गव कैमिकल्स, आंध्र प्रदेश, मै. जगदीश्वरी कैमिकल्स, आंध्र प्रदेश, मै. जया कैमिकल्स, आंध्र प्रदेश, मै. मुरुगनन्थम कैमिकल्स एंड कंपनी, तमिलनाडु, मै. राहुल बेरियम सॉल्ट, हैदराबाद तथा मै. आर. के. इंडस्ट्रियल कैमिकल्स, हैदराबाद द्वारा समर्थन किया गया है। रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन में समर्थकों सहित आवेदकों का हिस्सा सर्वाधिक है और वह भारतीय उत्पादन के 50% से अधिक है।

7. मै. विक्ट्री कैमिकल्स लि. ने वर्ष 2008-09 अर्थात् जाँच की अवधि के दौरान 53 मी. टन बेरियम कार्बोनेट का आयात किया है। यह दावा किया गया है कि ये आयात कम्पनी के फायर वर्क्स प्रभाग हेतु किए गए थे और इनका प्रयोजन व्यापारिक नहीं था।

उपर्युक्त के अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन आयातों की मात्रा काफी कम है और इसलिए उनके विचार से आवेदक को नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल न किया जाना आवश्यक नहीं है।

8. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार कुल घरेलू उत्पादन में आवेदकों का हिस्सा 42.89% है और आवेदन के समर्थकों के साथ कुल घरेलू उत्पादन में उनका हिस्सा 74.30% हो जाता है। अतः प्राधिकारी का निर्णय है कि यह आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) तथा नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है। इसके अतिरिक्त मै. अतियप्पा कैमिकल्स प्रा. लि., मै. एलाक कैम. इंडस्ट्रीज प्रा. लि., मै. प्रेम कैमिकल इंडस्ट्रीज तथा मै. विक्ट्री कैमिकल्स लि. को नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग माना जा रहा है।

शामिल देश

9. वर्तमान जाँच में शामिल देश चीन जनवादी गणराज्य (जिसे चीन जन. गण. भी कहा गया है) है।

सामान्य मूल्य

10. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमों के अनुरूप अनुबंध I के पैरा 7 एवं 8 के अनुसार किया जाना चाहिए। आवेदक ने निवेदन किया है कि चीन जन. गण. के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था के संबंध में वे पर्याप्त सूचना प्राप्त नहीं कर सके हैं। अतः आवेदक ने बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों एवं लाभ सहित उत्पादन की परिकलित लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है।

निर्यात कीमत

11. आवेदक ने आईबीआईएस द्वारा संकलित आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमतों का निर्धारण किया है। कारखाने द्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए निर्यात कीमतों में समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन हैंडलिंग, अंतर्देशीय परिवहन, वैट प्रतिपूर्ति हेतु समायोजन तथा बैंक कमीशन हेतु समायोजन किया गया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय भाड़ा, पत्तन प्रभार, पत्तन व्ययों तथा बैंक कमीशन के संबंध में कीमत समायोजनों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं।

पाटन मार्जिन

12. इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य, निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्ट्या यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

13. आवेदक ने कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति का दावा करते हुए साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। यह दावा किया गया है कि आयातों में समग्र अर्थों में और भारत में उत्पादन एवं खपत की तुलना में भी वृद्धि हुई है। आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में गिरावट आई है। आवेदक ने बिक्री, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सा, कीमत ह्रास, लाभ तथा लगाई पूंजी पर निवेश के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट का दावा किया है। संबद्ध देश से पाटित आयातों द्वारा आवेदक को हो रही क्षति के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य हैं जिससे पाटनरोधी नियमों के संदर्भ में इस जाँच की शुरुआत यथोचित है।

पाटनरोधी जाँच की शुरुआत

14. उपर्युक्त पैराग्राफों के मद्देनजर निर्दिष्ट प्राधिकारी पाते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति तथा पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद हैं और इसलिए पाटनरोधी जाँच करना उचित है। प्राधिकारी एतद्वारा उक्त नियम के नियम 5 के संदर्भ में घरेलू

उद्योग को हुए कथित पाटन एवं परिणामी क्षति के संबंध में कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा एवं प्रभाव की जांच करने हेतु पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करने हेतु एक जांच प्रारंभ करते हैं जिसे यदि लागू किया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी ।

जांच की अवधि

15. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक है तथापि क्षति जांच की अवधि में अप्रैल, 2005- मार्च, 2006, अप्रैल, 2006-मार्च, 2007, अप्रैल, 2007-मार्च, 2008 तथा जांच की अवधि (पीओआई) अर्थात् अप्रैल, 2008-मार्च, 2009 की अवधि शामिल होगी ।

सूचना प्रस्तुत करना

16. संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए, उनकी सरकार, भारत में संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी)

कमरा नं. 240, उद्योग भवन

नई दिल्ली-110107

17. कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र एवं ढंग से जांच से संगत अपने निवेदन प्रस्तुत कर सकती है ।

अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

18. पाटनरोधी नियम के नियम 7 के संदर्भ में हितबद्ध पक्षकारों को गोपनीयता का दावा करने के कारणों के साथ प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी भी गोपनीय सूचना का अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत करना अपेक्षित है । गोपनीय सूचना का अगोपनीय रूपांतर अथवा अगोपनीय सारांश पर्याप्ततः विस्तृत होना चाहिए ताकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सूचना का अर्थ स्पष्ट हो सके । यदि ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार से विचार से, सूचना का सारांश नहीं किया जा सकता; तो उसके कारण बताते हुए एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा ।

उपर्युक्त पैरा में किसी बात के होते हुए भी यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता हेतु अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा सूचना प्रस्तुत करने वाला सूचना को सार्वजनिक करने हेतु सामान्य रूप से अथवा सारांश में उसके प्रकटन हेतु इच्छुक नहीं है तो ऐसी सूचना को नजरअंदाज कर सकते हैं ।

समय सीमा

18. इस जांच से संबंधित कोई सूचना तथा सुनवाई हेतु कोई अनुरोध लिखित में इस प्रकार भेजा जाए कि वह ऊपर लिखित पते पर प्राधिकारी के पास, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर पहुँच जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार “उपलब्ध तथ्यों” के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

19. नियम 6(7) के अर्थों के भीतर कोई हितबद्ध पक्षकार दूसरे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना, साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण वाली फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

“उपलब्ध तथ्यों” का उपयोग

20. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उचित अवधि के भीतर उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को उचित सिफारिश कर सकते हैं।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2009

Subject : Initiation of Anti-Dumping investigation concerning imports of 'Barium Carbonate originating in or exported from China PR.

No. 14/18/2009-DGAD.—M/s Athiappa Chemicals Pvt. Ltd., M/s. Ellak Chem Industries Pvt. Ltd., M/s. Prem Chemical Industries and M/s. Victory Chemicals Ltd. have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) alleging dumping of 'Barium Carbonate' (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as subject country) and have requested for initiation of anti-dumping investigation and levy of anti-dumping measures.

Product under consideration

2. The product under consideration is 'Barium Carbonate'. Barium Carbonate is a harmful, non-flammable inorganic chemical in the form of a white powder and granules having chemical formula BaCO₃ manufactured out of Barytes, a mineral product. Barium Carbonate has the following applications:

- (a) Purification of brine solution in caustic soda industry.

- (b) In production of Hard Ferrite Ring Magnets, Television Glass Shell, Neutral glass, Lamps, Heat treatment salts and other barium salts, rat poison, ceramic glazes and welding flux.
- (c) Acts as a flux, matting and crystallizing agent and combines with certain colouring oxides to produce unique colours not easily attainable by other means.
- (d) In the manufacture of heavy clay ceramic products because of its property of converting soluble sulfuric salts in the raw material into insoluble barium sulfate.
- (e) In the brick, tile, earthenware and pottery industries barium carbonate is added to clays to precipitate soluble salts (calcium and magnesium sulfates) that cause efflorescence.

3. The products under consideration is an inorganic chemical falling under Chapter 28. It is imported under subheading 28366000 of Chapter 28 under the Customs Classification. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.

Domestic Like Article

4. The applicant has claimed that there is no significant difference in subject goods produced by the domestic industry and exported from subject country. Subject goods produced by the Indian industry and imported from subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and consumers have used the two interchangeably.

5. For the purpose of investigation, the subject goods produced by the applicants are being treated as like articles to the subject goods imported from subject country within the meaning of the Anti-dumping Rules for the purpose of this investigation.

Domestic Industry & 'Standing'

6. The application has been filed by M/s Athiappa Chemicals Pvt. Ltd., M/s. Ellak Chem Industries Pvt. Ltd., M/s. Prem Chemical Industries and M/s. Victory Chemicals Ltd on behalf of the domestic industry. The applicant domestic producers have provided injury and costing information. The application has been supported by a number of domestic producers of the like Article, namely M/s. Amaravathi Chemicals & Fertilizers Pvt. Ltd., Hyderabad; M/s Bhargav Chemicals, Andhra Pradesh; M/s Jagadeeshwari Chemicals, AP; M/s Jaya Chemicals, Andhra Pradesh; M/s. Muruganantham Chemical & Co., Tamil Nadu; M/s Rahul Barium Salts, Hyderabad and M/s R.K. Industrial Chemicals, Hyderabad. As per the evidence available on record, production of the applicants along with the supporters account for a major proportion of the domestic production and the same is more than 50% of the Indian production.

7. M/s. Victory Chemicals Ltd has imported 53 MT of Barium Carbonate 2008-09 viz. during the period of investigation. It has been contended that these imports were for Fire Works Division of the company and were not meant for trading purposes.

Besides the above, the Authority notes that the volume of these imports are quite small, and therefore considers it appropriate to hold that the Applicant is not required to be excluded from the scope of the domestic industry under Rule 2(b).

8. As per information available on record, the Applicants account for 42.89% of the total domestic production and along with the supporters of the application, they account for 74.30% of the total domestic production. Thus, the Authority has determined that the application satisfies the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules. Further, M/s Athiappa Chemicals Pvt. Ltd., M/s. Ellak Chem Industries Pvt. Ltd., M/s. Prem Chemical Industries and M/s. Victory Chemicals Ltd are being treated as 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b).

Country involved

9. The country involved in the present investigation is the People's Republic of China (also referred to as China PR).

Normal value

10. The applicant has claimed that China PR should be treated as Non Market Economy and therefore the Normal value should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annex-I of the AD Rules. The applicant has submitted that they have not been able to get the sufficient information regarding market economy third country for determination of Normal value in case of China PR. Thus, the applicant has claimed the Normal value on the basis of constructed cost of production, including selling general and administration expenses and profits.

Export Price

11. The applicant has determined export prices based on the data compiled by IBIS. The export prices have been adjusted for ocean freight, marine insurance, commission, port handling, inland transportation, adjustment for VAT refund and bank commission to arrive at net export price at ex-factory level. Evidence in support of price adjustments has been provided in respect of Ocean Freight, Marine Insurance, Commission, Inland Freight, Port Expenses and Bank Commission.

Dumping margin

12. There is sufficient evidence that the Normal value of the subject goods in subject country is significantly higher than the net Export price, prima-facie indicating that the subject goods are being dumped by the exporters from the subject country.

'Injury' and Causal Link

13. The applicant has furnished evidence claiming injury as a result of alleged dumping. It has been claimed that the imports have increased in absolute terms and in relation to production & consumption in India; the imports are undercutting the prices of the domestic industry. The applicant has claimed deterioration in performance of the domestic industry in terms of sales, production, utilization of capacity, market share, price suppression, profit and return on capital employed. There is sufficient evidence with regard to 'injury' being suffered by the applicant caused by dumped imports from subject country to justify initiation of this investigation in terms of the AD Rules.

Initiation of Anti Dumping Investigation

14. In view of the foregoing paragraphs, the Designated Authority finds that sufficient evidence of dumping of subject goods from the subject country, 'injury' to the domestic

industry and causal link between the dumping and 'injury' exists to justify initiation of an anti-dumping investigation. The Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent 'injury' to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping measure, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Period of investigation

15. The period of investigation for the purpose of present investigation is 1st April 2008 to 31st March 2009. The injury investigation period will, however, cover the periods April 2005-March 2006, April 2006-March 2007, April 2007-March 2008 and the Period of Investigation (POI) v iz. April 2008 - March 2009.

Submission of information

16. The known exporters in subject country, their government through their Embassy in India, the known importers and known users in India to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

The Designated Authority,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties, (DGAD),
Room No. 240, Udyog Bhawan,
New Delhi - 110107.

17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

Submission of information on Non-confidential basis.

18. In terms of Rule 7 of the AD rules, the interested parties are required to submit non-confidential version of any confidential information provided to the Authority along with the reasons for claiming confidentiality. The non-confidential version or non-confidential summary of the confidential information should be in sufficient detail to provide a meaningful understanding of the information to the other interested parties. If in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summary; a statement of reason thereof is required to be provided.

Notwithstanding anything contained in para above, if the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information.

Time limit

18. Any information relating to this investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the above mentioned address, not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the 'facts available' on record in accordance with the AD Rules.

Inspection of Public File

19. In terms of Rules 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the information/evidence submitted by other interested parties.

Use of 'facts available'

20. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the 'facts available' to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

R. GOPALAN, Designated Authority